

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

मंगलवार 2 दिसंबर 2025

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

दिल्ली वायु प्रदूषण पर SC में सुनवाई, केंद्र सरकार से मांगा गया एक्शन प्लान

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और संबंधित अधिकारियों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अपनी कार्ययोजना पर फिर से विचार क्यों नहीं करते ताकि खुद देख सकें कि क्या आपने कोई प्रभावी बदलाव लाए हैं? और अगर लाए हैं, तो क्या वे जरूरत से कम हैं? हमें लगता है कि यह मूल्यांकन करना जरूरी है कि आपकी कोई भी कार्ययोजना प्रभावी, अप्रभावी या कम प्रभावी साबित हुई है या नहीं। इस बारे में आपकी हिचकिचाहट या

आत्मविश्वास के बावजूद कि क्या आप प्रभावी बदलाव ला पाएंगे, क्या कार्ययोजना पर फिर से विचार करना सही नहीं है? अब तक आपने जो कदम उठाए हैं, उनका मूल्यांकन करें। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि पराली जलाने के अलावा और कौन से कारक वायु प्रदूषण में वृद्धि में योगदान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस वर्ग (किसानों) पर दोष मढ़ना बहुत आसान है जिनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे पराली जलाने के अलावा अन्य कारकों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी विचार करने की आवश्यकता है। पराली



जलाना तो आम बात थी। 4-5 साल पहले लोग नीला आसमान क्यों देख पाते थे? अब क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह

वायु प्रदूषण मामले की हर महीने कम से कम दो बार सुनवाई करेगा। इसने स्वीकार किया कि सदियों के मौसम

के बाद स्थिति शांत हो सकती है, लेकिन इस संबंध में, "इतिहास खुद को दोहराएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी। जबकि न्यायालय प्रदूषण नियंत्रण में व्यवस्थागत खामियों पर विचार-विमर्श कर रहा था, दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 299 हो गया, जो रविवार शाम 4 बजे 279 था। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दो दिनों से वायु गुणवत्ता "खराब" दर्ज की जा रही है, जबकि रविवार को यह "बहुत खराब" श्रेणी में थी। शनिवार को एक्यूआई 305 से घटकर 279 हो गया था।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में होगी ऐतिहासिक बहस,

मोदी के भाग लेने की संभावना



नई दिल्ली वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सप्ताह के अंत में लोकसभा में एक विशेष चर्चा आयोजित होने की संभावना है। इस अवसर पर सदस्यों को स्वतंत्रता आंदोलन में इस देशभक्ति गीत की भूमिका और इसकी समकालीन प्रासंगिकता के अलावा भारत की सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चर्चा में भाग लेने की संभावना है। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सप्ताह के अंत में लोकसभा में एक विस्तृत और विशेष चर्चा आयोजित होने की संभावना है।

सांसद ने बताया कि यह चर्चा संसद के शीतकालीन सत्र का एक प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका और समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस चर्चा में भाग लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह चर्चा उस रचना को उजागर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाएगी, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनिर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है और जो भारत की राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का एक स्थायी प्रतीक है।

SIR पर बवाल

विपक्ष का जोरदार हंगामा,

उच्च सदन में सभापति का जोरदार स्वागत



नई दिल्ली संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। विपक्षी सांसदों द्वारा बार-बार की गई नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसदों की मुख्य मांग देश भर में मतदाता सुविधों से संबंधित विरोध गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा कराना था। वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के आरंभ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन का हार्दिक स्वागत किया। राधाकृष्णन पहली बार उच्च सदन की अध्यक्षता करने के लिए संसद पहुंचे, जिससे उनके अध्यक्ष पद पर कार्यकाल की शुरुआत हुई। लोकसभा की कार्यवाही संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दो सोमवार को लोकसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कुछ

अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित रही और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही लोकसभा ने मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और हस्वस्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश किया। बैठक शुरू होने पर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को कुछ दिवंगत पूर्व सदस्यों

और हमें अच्छी परिपाटियां और परंपराएं स्थापित करनी चाहिए। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि पिछले पांच साल में संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए असम में 2,900 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मिला दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 41,455 करोड़ रुपए के शुद्ध अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मांगी जिसमें से 27,000 करोड़ रुपये से अधिक उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से जुड़ा व्यय शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश किया। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार समान बनाए रखने के लिए सोमवार को दो विधेयक लोकसभा में पेश किए।

भगोड़े आर्थिक अपराधियों का राज खुला

15 पर 58,000 करोड़ की देनदारी, विजय माल्या और नीरव मोदी का भी नाम

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कुल 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह जानकारी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा सदस्य और दौसा से कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा द्वारा उठाए गए एक अतारफित प्रश्न के उत्तर में साझा की गई। मीणा ने लोकसभा में वित्त मंत्री से

पूछा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत आज तक कितने व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए गए वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में; इन घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हुई कुल वित्तीय हानि (रुपये में) का विवरण, नाम-वार और बैंक-वार; निपटान में शामिल व्यक्तियों का नाम और संख्या, संबंधित बैंकों के नाम, निपटाई गई राशि और दी गई



छूट। चौधरी ने कहा कि इन 15 अपराधियों में से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर

की गई वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हैं। इस सूची में विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वित्त राज्य

मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इन 15 भगोड़े आर्थिक अपराधियों (FEO) ने सामूहिक रूप से 31 अक्टूबर, 2025 तक बैंकों को 26,645 करोड़ रुपये का मूल वित्तीय नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा, इन ऋणों पर एनपीए बनने की तिथि से 31 अक्टूबर, 2025 तक अर्जित ब्याज 31,437 करोड़ रुपये है।

चौधरी ने सदन को बताया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक इन अपराधियों से 19,187 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

गुटखा-पान मसाला पर कड़ा प्रहार!

नई दिल्ली जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया के दौरान तंबाकू से संबंधित वस्तुओं पर 'सीन टेक्स' लगाने के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 'स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025' पेश किया। इस विधेयक में रक्षा और जन स्वास्थ्य व्यय के वित्तपोषण के लिए पान मसाला और गुटखा निमार्ताओं पर एक कटौत नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक के अनुसार, प्रस्तावित उपकर पान मसाला और गुटखा सहित विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के लिए स्थापित



मशीनों या प्रक्रियाओं पर लगाया जाएगा। इसमें कहा गया है, "स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक में उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने का प्रस्ताव है जिनके द्वारा निर्दिष्ट वस्तु,

अर्थात् पान मसाला, का निर्माण या उत्पादन किया जाता है, चाहे वह मैनुअल रूप से हो या हाइब्रिड प्रक्रियाओं के माध्यम से।" यह विधेयक एक व्यापक अनुपालन और प्रवर्तन ढांचा प्रस्तुत करता है।

'कुंडी खटकाओ' से बदलेगा यूपी का चुनावी समीकरण? बीजेपी की घर-घर दस्तक



उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लखनऊ में 'कुंडी खटकाओ' नामक घर-घर अभियान शुरू करके मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई इलाकों में घरों तक पहुंचकर निवासियों से मतदाता पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी करने और इस पाददर्शी एवं आवश्यक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने का आग्रह किया। इस अभियान का नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता संशोधित मतदाता सूची में शामिल हो। उन्होंने कहा कि आज, विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत, हम घर-घर जाकर लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने और अपने फॉर्म भरकर जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चौधरी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और उस पर मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक आशंकाएं पैदा करने का आरोप लगाया।

यूपी में अवैध घुसपैटियों को अब खैर नहीं

सीएम योगी के निर्देश पर सड़कों पर उतरी पुलिस

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अवैध घुसपैटियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद सोमवार को राजधानी लखनऊ में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस टीम ने सरोजनी नगर क्षेत्र में उन लोगों पर फॉक्स किया जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पुलिस ने जब इन लोगों के आधार चेक किए तो कान खड़े हो गए। इनमें ज्यादातर के आधार कार्ड असम के बने हुए हैं। पुलिस अब इन पहचान पत्रों की श्री लेयर चेंकिंग करेगी, अगर एक भी व्यक्ति अवैध रूप से रहता मिला तो उसे यहां से बाहर खदेड़ा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कम्प मचा रहा।

ज्यादातर कार्ड असम से बने-कई साल से रहने का दावा पुलिस ने सरोजनी नगर और उसके आसपास कूड़ा बीनने वालों की चेंकिंग की। इनमें ज्यादातर के पास असम से बने आधार कार्ड थे, पृष्ठताछ में कुछ ने बताया कि वो 1 से 2 साल पहले ही यूपी आए हैं, जबकि कई ने 20-25 साल से यहीं रहने की बात कही। पुलिस ने सबही के कागजात जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब होगा श्री-लेयर वैरिफिकेशन लखनऊ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड चूँकि असम के बने हैं अब श्री लेयर वैरिफिकेशन से स्पष्ट हो सकेगा कि यह सही हैं या नहीं। सभी के मूल पते



पर सम्पर्क कर वहां थाना पुलिस ने पता लगाया जाएगा यह व्यक्ति वास्तविक में वहां

का निवासी है या नहीं। कब तक वहां रहा और फिर कब से गायब है। इसके साथ ही

आधार जारी करने वाले एजेंसी से भी जांच करवाई जाएगी, अधिकारी ने बताया कि अगर आधार और पहचान पत्र फर्जी पाए गए तो इन पर अवैध घुसपैठ के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी का सख्त रुख-घुसपैठि होंगे बाहर यहां बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कहन भी संदिग्ध या अवैध नागरिक नहीं रहने चाहिए, जांच कर इनपर कार्रवाई होनी चाैये, जिसके बाद यूपी पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ के बाद जल्द ही अन्य शहरों में भी यह अभियान शुरू किया जाएगा।

महिला का बैग काटकर जेवर उड़ाने वाले दो शातिर चढ़े पुलिस के हत्थे, एक लाख की झुमकी, 36 हजार कैश और आठो बरामद

अखंड भारत संदेश

शंकरगढ़। एसओजी यमुनानगर व शंकरगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने बैग काटकर ज्वेलरी चोरी करने वाले आठो गैंग के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की एक जोड़ी झुमकी (कीमत लगभग एक लाख रुपये), हार बेचकर प्राप्त 36 हजार रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त आठो UP70HT8950 बरामद किया गया। थाना प्रभारी यशपाल सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की।



थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को अभियुक्तों के गतिविधियों के महत्वपूर्ण इन्पुट मिले। प्रयागराजइंचित्रकूट मार्ग की नहर पुलिया पॉवर प्लांट के पास से मो. चांद पुत्र इनायत खां निवासी बुंदवा थाना घूरपुर तथा राजेश पुत्र राधेश्याम निवासी कोटवारन का पुरवा थाना बारा को गिरफ्तार कर लिया गया। छल्लेखनीय है कि 29 नवंबर को वादिनी सुधा सिंह निवासी मोटियान टोला ने तहरीर देकर बताया था कि



आठो चालक सहित तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनका बैग काटकर जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीमों को लगाया, जिसके बाद मात्र 24 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि 21 नवंबर को रेलवे फाटक के पास एक महिला व बच्ची को आठो में बैठाकर उनका बैग पीछे रखा गया था। दोनों ने बैग को घेरकर बैठे हुए मौका देखकर बैग काटकर सोने

की झुमकी व सोने का हार चोरी किया था। हार बेचने पर प्राप्त 36 हजार रुपये भी बरामद कर लिए गए।गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम में उ.नि. कृष्णकांत तिवारी, उ.नि. गौरव यादव, हे.का. अरविंद तिवारी, हे.का. मंदेश सरोज, एसओजी यमुनानगर जोन के

उ.नि. नवीन कुमार सिंह (प्रभारी), का. दीपक सिंह, का. सिद्धेश्वर पांडेय, का. लकी यादव, का.अजय सिंह, का. मनोज कुमार यादव, का. शशिकांत यादव तथा सर्विलांस सेल के उ.नि. प्रमोद कुमार यादव व का. अजय सिंह शामिल रहे।

पंडित विजयलक्ष्मी की मनाई गई पुण्यतिथि

सहस्रों। काग्रेस गंगापार के जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में भारद्वाज गुरुकुलम संस्थान में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनायक और कुशल प्रखर वक्ता और वरिष्ठ राजनीतिक पंडित विजयलक्ष्मी जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करके मनाई गई।अहमद ने कहा कि पंडित विजयलक्ष्मी वरिष्ठ वकील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू की बेटी तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं वह एक कुशल और प्रखर वक्ता के साथ-साथ महान संगीतज्ञ थीं। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली



निर्वाचित महिला सदस्य रही जो बाद में 1953 से 1954 तक संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष रहें। और बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने कार्य को संचालित किया और देश का मान बढ़ाया वे 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा

की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव भी उन्होंने को है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया था वह भारत की पहली महिला राजदूत थी जो मास्को

वाशिंगटन और लंदन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल का दायित्व भी संभाला हमको आपको उनके द्वारा किए गए कार्यों और योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें उनके आदर्श और शिक्षाओं को आत्म शांत करना चाहिए।कार्यक्रम का संचालन विधानसभा प्रभारी देवराज उपाध्याय ने किया।इस अवसर पर सर्वश्री सलीम टाइगर, श्याम जी धुरिया, सरस्वती कुशवाहा, रेशमा यादव, शर्मिला कुशवाहा, रुचि यादव, रितिका मिश्रा, गौरव श्रीवास्तव, शुभम यादव, संदीप भारतीया आदि लोग उपस्थित रहे।

वाहन ओवरटेक के विवाद में सेना के जवान विवेक सिंह की स्कार्पियो सवारों ने की हत्या

● अपनी चचेरी बहन की शादी में छुट्टी लेकर अपने एक दोस्त के साथ घर आया था फौजी

● पाच आरोपियों को एसओजी टीम ने 4 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार



वर्षीय विवेक सिंह पुत्र उमाकांत सिंह दिल्ली में सेना में तैनात थे। 29 नवंबर को चचेरी बहन की शादी में शामिल होने वह घर आए थे। शादी की रात वह अपने दोस्त कोहड़ार है बाजार निवासी विनय जैन को गांव के ही करण सिंह के साथ कार से कोहड़ार बाजार छोड़ने गए थे। लौटते समय धरवारा मोड़ के पास बारात से लौट कर स्कार्पियो सवार युवकों से ओवरटेक को लेकर कहासुनी हो गई थी। मौके पर लोगों ने मामला शांत करा दिया लेकिन जैसे ही विवेक कार में बैठने लगे, स्कार्पियो में सवार

युवकों ने खींचकर उन्हें पीटने लगे। तभी अचानक पीछे से उनके सिर पर भारी वस्तु से वार कर दिया। विवेक मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें पहले करछना सीएफएस और वहां से रेफर होने पर लखनऊ के मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। जहां सोमवार भोर करीब तीन बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक दो भाइयों में छोटा था। परिवार में पत्नी प्रतिभा और तीन वर्षीय पुत्र वेदांत का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मिर्जापुर में तैनात दरोगा राजकमल पांडेय, स्कार्पियो मालिक दिनेश कुमार यादव, राजीव कुमार ठाकुर, राजू अग्रहरि और भाई लाल यादव निवासीगण चकराना तिवारी नैनी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव के निर्देश पर गठित एसओजी और करछना पुलिस टीम ने फौजी की मौत के चार घंटे के भीतर ही सभी आरोपी दबोच लिए। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

वाइक की टक्कर से पल्लेदार की मौत

बारा। बारा थाना क्षेत्र के गन्ने चौकी रविवार रात्रि गन्ने से ककरहा नहर पर अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक सवार एक पल्लेदार की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेज दिया है।उमेश आदिवासी (27)पुत्र राम अधीन आदिवासी निवासी ग्राम बांसी ककरहा पहाड़ थाना बारा गन्ने नारीबारी में पल्लेदारी करता था। वह हमेशा की तरह रविवार रात नारीबारी से पल्लेदारी का काम करके घर पैदल आ रहा था। नहर पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात ने टक्कर मार दिया। स्थानीय लोग उसे एक स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए और पुलिस को सूचना दी।हालत गंभीर होने के कारण वहां भर्ती नहीं किया गया।उसे नारीबारी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक के नाक से रक्त श्राव होना व दाहिने पंजे की उंगली कुंची हुई दिख रही थी। मौके से एक बाइक भी मिली है।उसे गन्ने चौकी में खड़ी कर दिया गया है।परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एस आई एम नर्सिंग कॉलेज द्वारा विश्व एड्स दिवस पर निकली जागरूकता रैली

● जागरूकता का मुख्य उद्देश्य ही लोगों में सन्देश देना : डायरेक्टर इंजी एल बी मौर्या

● थाना थरवई मिशन शक्ति टीम भी मौजूद : किया जागरूक

लोगों को समय पर जाँच व उपचार के लिए प्रेरित करती है। एचआईवी हाथ मिलाने या गले लगाने से, भोजन, पानी व बर्तन साझा करने से एवं शौचालय, स्कूल, ऑफिस व कपड़े से नहीं फैलता है बल्कि एचआईवी ब्लड ट्रांसफरेशन, असुरक्षित यौन सम्बन्ध, संक्रमित सुई या सिरिज का उपयोग में लाने से फैलता है। एसआईएम नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका ज्योति गुप्ता, अकिता, आराध्या ने रैली में उपस्थित रहते हुए बताया की एचआईवी / एड्स वाले लोगों को अक्सर समाज में मतभेद का सामना करना पड़ता है और उन्हें सम्मान नहीं मिलता है। वे इलाज लेने के लिए छिपाते हैं। जिसके लिए रैली के माध्यम स्वागत जागरूक किया गया। इस रैली में एस आई एम नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिकायें, छात्राएँ, एस आई एम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल दीपा, इम्पेक्टर थरवई संतोष कुमार पाण्डेय के निर्देशन में अतिरिक्त निरीक्षक पारस नाथ, थाना



थरवई मिशन मिशन शक्ति टीम में महिला मोना कौशल आदि मौजूद रहीं और उन्हें एस आई दीप्ती मिश्रा, आकांक्षा द्विवेदी, जागरूक भी किया।

सचिवों ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया

प्रयागराज जिलाधिकारी को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा

अखंड भारत संदेश



मांडा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में कार्यरत क्षेत्रीय सचिवों (GPA/GVA) ने ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रयागराज जिलाधिकारी को चार सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश शासन ने 3 नवंबर 2025 को एक शासनानुदेश जारी कर ग्राम पंचायतों में कार्यरत क्षेत्रीय सचिवों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। डीपीआरओ आगरा द्वारा यूपी पीआरडी पोर्टल पर फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम (FRS) और जिओ-फेंड AI-ML अटेंडेंस प्लेटफॉर्म से संबंधित पीपीटी भी जारी की गई है। सचिवों का आरोप है कि निदेशक पंचायतीराज या आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा अभी तक कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए

गए हैं। इसके बावजूद, प्रदेश के कुछ विकास खंडीय और जनपदीय अधिकारियों ने अपने अधीनस्थों पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जबकि उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए ' इस क्रम में, सचिवों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्रमिक और शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा की

है। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की अवधि 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के तहत, 15 दिसंबर 2025 को प्रदेश के सभी सचिव अपनी क्लस्टर की समस्त ग्राम

पंचायतों के डोंगल अपने संबंधित विकासखंड पर एकत्रित होकर पूर्वाह्न 11 बजे सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यालय में जमा करेंगे। यह विरोध ई-ग्राम स्वराज के जटिल गेटवे सिस्टम की भुगतान प्रणाली के खिलाफ है, जिसके लिए वे एक एकीकृत मोबाइल ऐप/ वेबसाइट/ पोर्टल के निर्माण की मांग कर।

एस आई आर फॉर्म जमा करने जा रहे व्यक्ति की हादसे में मौत

राह सों । जगबन्धनपुर गांव निवासी राी ओ डी छिवकी से सेवानिवृत्त 65 वर्ष के रामचंद्र पुत्र मखदूम प्रसाद रविवार की सुबह विशेष ग्रहण पुनरीक्षण फॉर्म जमा करने के लिए कसगांव जा रहे थे। जैसे ही वह भोपतपुर गांव के सामने पहुंचे कि फूलपुर की तरफ से आ रही अनियंत्रित बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथ चल रहे उनके साथी देशराज ने तत्काल इसकी सूचना परिजनों के दी। मौके पर पहुंचे परिजन उन्हें प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां पर इलाज के दौरान रविवार को लगभग दोपहर बाद 2:00 बजे उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के पश्चात परिजनों ने रात में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनकी मौत से पत्नी सुशीला पुत्र अरुण कुमार सहित अन्य लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विकास खंड करछना के ग्राम पंचायत सचिवों ने सामूहिक रूप से काली पट्टी बांधकर सरकार के दबाव पूर्ण कार्यों का किया विरोध



अखंड भारत संदेश

करछना। विकास खंड करछना में ग्राम पंचायत सचिव संजीव श्रीवास्तव, दीप्ति मिश्रा, ममता पाण्डेय, जुही सिंह, प्रियम देवी, गरिमा यादव, नेहा, मनीष सिंह, प्रफुल्ल सिंह, अक्षत सिंह, आशीष सिंह सहित विकास खण्ड करछना में तैनात समस्त सचिवों ने सामूहिक रूप से जताया विरोध उपस्थिति और गैर-विभागीय कार्यों के विरोध में ग्राम पंचायत सचिवों का प्रदेशव्यापी सचवाई चरणबद्ध सत्याग्रह-1 से 15

दिसंबर तक तगड़ा आंदोलन... उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों ने सरकार को कड़ा संदेश देते हुए ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम और गैर-विभागीय कार्यों के बोझ के खिलाफ उठाया बड़ा कदम... 1 से 4 दिसंबर 2025-सचिव काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्य करेंगे-प्रतीकात्मक विरोध की शुरुआत। 5 दिसंबर -प्रदेश भर में सचिव धरने पर बैठेंगे, साथ ही सभी सरकारी क्वाटर्सेएप समूहों से सामूहिक रूप से लेफ्ट हो जाएंगे-प्रशासनिक तंत्र के

लिए बड़ा झटका.. 10 दिसंबर -सभी सचिव निजी वाहन उपयोग पूरी तरह बंद कर देंगे-फील्ड कार्य ठप होने की संभावना.. 15 दिसंबर 2025-सचिव अपने डोंगल ब्लॉक कार्यालय में जमा करेंगे-तकनीकी कार्य प्रभावित होने की आशंका.. ग्राम विकास अधिकारी करछना संजीव श्रीवास्तव ने साफ कहा-इस सचिव बोझिल कार्यप्रणाली और अव्यवस्थित ऑनलाइन सिस्टम का दबाव नहीं झेलेंगे। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन और तेज होगा।

बाइक बाइक में आमने-सामने से टक्कर एक की हालत गंभीर दूसरा चोटिल



नैनी। नैनी स्टेशन रोड के समीप पुल के सामने रविवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। जहां तेज रफ्तार दोनों बाइक सवार आमने सामने से भिड़ गए टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों की भिड़ंत की आवाज हनुमान नगर तक गूंज उठी। जब घटना स्थल पर लोग दौड़कर पहुंचे तो दोनों युवक घायल होकर तड़प रहे थे। स्थानीय लोगों ने तत्काल नैनी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची नैनी पुलिस ने दोनों घायलों को अरैल मोड़ स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार एक. सी. आई. निवासी साजन व चीनीमिल

निवासी विजय कुमार नैनी स्टेशन रोड से गुजर रहे थे लेकिन महाकुंभ में बनी सड़क पर पानी जमा होने के कारण किनारा काटते हुए युवक तेज रफ्तार से निकल रहे थे उसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार युवक ने एक दूसरे को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे साजन के कई दांत टूटकर बाहर आ गए और चेहरे में भयानक रूप से सूजन बन गई वहीं विजय कुमार को भी मामूली रूप से चोट लगी है। सूचना पर पहुंची नैनी पुलिस ने ई रिक्शा की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचवाया और क्षतिग्रस्त दोनों बाइक को नैनी कोतवाली भिजवाया।

सरायममरेज पुलिस ने नाबालिग छात्रा को 48 घंटे में अपहरणकर्ता से कराया मुक्त

अखंड भारत संदेश



जंघई। थानाध्यक्ष सरायममरेज अतुल मिश्रा एवं उनकी टीम की तेज तर्रार, कुशल कार्यशीली से सीडीआर, सीसीटीवी इन्पुट के माध्यम से महज 48 घंटे में ही दसवीं कक्षा की छात्रा को बरामद करते हुए अपहरण करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में सरायममरेज थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा ने कहा कि नाबालिग छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाई की जाएगी। छात्रा के परिजनों ने बताया कि 27 नवंबर को सुबह 8:45 पर छात्रा घर से आदिशक्ति इंटर कालेज पढ़ने गई थी जहां से छात्रा का अपहरण कर लिया गया। छात्रा के परिजनों ने जब स्कूल के प्रधानाचार्य से पूछताछ किया तो पता चला कि दो लड़के आये और

बोले कि तुम्हारी मम्मी की तबियत ज्यादा खराब है इसके बाद प्रधानाचार्य ने छात्रा को छुट्टी दे दिया, छात्रा के परिजनों ने प्रधानाचार्य की मिलीभगत से छात्रा का अपहरण करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के प्रार्थना पत्र पर सरायममरेज पुलिस मुकदमा दर्ज करके जाँच पड़ताल में जुट गई और सरायममरेज पुलिस ने 48 घंटे में ही इस मामले का खुलासा कर दिया। परिजनों ने छात्रा के साथ अनहोनी का आशंका जताई है।

अधिवक्ताओं ने कस्सी कमर 82 प्रतिशत मतदाता पुनरीक्षण फार्म की हुई फीडिंग

बारा। बारा तहसील में चल रहे सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं द्वारा बूथ बूथ जा कर स्वयं कार्य किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बारा तहसील में डिजिटाइजेशन 82 प्रतिशत पहुंच गया है। सोमवार को एसडीएम बारा प्रेरणा गौतम द्वारा लखनपुर और गोंदलापुर बूथों पर पहुंच कर स्वयं मतपत्रों से फीडिंग की गई। रविवार को बारा तहसील में फीडिंग की प्रगति 72 प्रतिशत रही और चौबीस घंटे में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 82 प्रतिशत पहुंच गई। इस संबंध में एसडीएम बारा ने कहा कि सघन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम तहसील के सभी अधिकारियों और बीएलओ की सामूहिक उत्तरदायित्व है। सभी अधिकारी तहसीलदार,नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और खंड विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। यद्यपि कि निर्वाचन आयोग ने



समय सीमा बढ़ा दिया है फिर भी हमारा प्रयास है

कि निश्चित समय सीमा में काम पूरा हो जाय।

माघ मेला 2026 में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के दृष्टिगत मंडलायुक्त तथा पुलिस कमिश्नर की संयुक्त अध्यक्षता में ट्रैफिक मूवमेंट प्लान संबंधित बैठक संपन्न

मेला अवधि में जनपद की यातायात व्यवस्था और बेहतर करने हेतु टैक्सी एवं मिनी बसों को अधिक मात्रा में चलाने पर भी चर्चा

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। माघ मेला 2026 में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के दृष्टिगत मंडलायुक्त सोम्या अग्रवाल तथा पुलिस कमिश्नर जोगिंदर सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित आई ट्रिपल सी सभागार में पुलिस, परिवहन, मेला तथा जिला प्रशासन के सभी संबंधित अधिकारियों की ट्रैफिक मूवमेंट प्लान की बैठक संपन्न हुई जिसमें सर्वप्रथम मण्डलायुक्त ने गूगल के अधिकारियों से वार्ता करते हुए माघ मेले के सभी प्रमुख मार्गों, स्नानघाटों, पार्किंग स्थलों, अन्य मुख्य स्थानों तथा ड्रायवर्जन रूट्स को मेला अवधि में गूगल मैप में



प्रदर्शित करने पर चर्चा की। इस पर गूगल के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया की इस कार्य हेतु रोड मैनेजमेंट इनसाइट (आरएमआई) का प्रयोग किया जा सकता है एवं गूगल मैप्स की टीम मेला प्रशासन की टीम के साथ अग्रतर कार्रवाई हेतु शीघ्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के

माध्यम से जुड़ेगी। रोड मैनेजमेंट इनसाइट (आरएमआई) गूगल मैप्स प्लेटफॉर्म की एक सेवा है जो सड़क और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए ट्रैफिक की गति, अवधि और भीड़भाड़ संबंधी डेटा प्रदान करती है। मेला अवधि में जनपद की यातायात व्यवस्था और बेहतर करने हेतु टैक्सी एवं मिनी बसों को अधिक मात्रा में चलाने पर भी चर्चा की गई। मेला प्रशासन पहले ही टैंडर के माध्यम से ओला, ऊबर एवं रैपिडो जैसी कंपनियों को आबद्ध करने हेतु कार्य प्रारंभ कर चुका है। पानी में डूबने की घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत जल पुलिस द्वारा कराई जा रही व्यवस्था की जानकारी ली गई जिसपर संबंधित अधिकारियों ने अवगत कराया कि

इस बार 40 गोताखोरों के साथ-साथ 6 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की एक-एक टीम भी पेट्रोलिंग करते हुए सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी। श्रद्धालुओं से नाविक अधिकारियों को लें यह सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्माण विभाग के अधिकारियों को नाविकों से अपनी नावों पर अनुमत्य दूर एवं हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य रूप से प्रिंट करवाने के निर्देश दिए गए जिसे देखने के बाद ही वे टेस्टिंग सर्टिफिकेट जारी करेंगे। यदि कोई नाविक सर्टिफिकेट के बिना नाव चलाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साइनेज व्यवस्था को और बेहतर करने के दृष्टिगत बनाई गई समिति

द्वारा शहर एवं अन्य जनपदों से जुड़े मुख्य मार्गों पर गैप्स का चिन्हांकन करते हुए साइनेज लगवाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र में आग की घटनाओं को रोकने अथवा घटनाएं होने पर उन्हें बुझाने का रिसपांस टाइम और कम करने के दृष्टिगत विभिन्न सेक्टरों में अग्निशमन गाड़ियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में एडिशनल कमिश्नर पुलिस डॉ॰ अजयपाल, मेला अधिकारी ऋषिराज, पुलिस अधीक्षक मेला नीरज पांडेय, अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे।

निडरता : जिलाधिकारी और एसडीएम को भी नहीं डरते लेखपाल

लोकल लेखपाल होने से जनता, और ग्राम प्रधानों, गरीबों, का नहीं हो पा रहा कोई कार्य

अखंड भारत संदेश

कोरांव। सरकारी संस्थाओं की भूमि संपत्तियां चाहे अवैध कब्जे की हों या उन्हें भू माफियाओं से मुक्त करा कर भूमि आवास हीनों को आवंटित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के मामले हों कुछ ऐसे राजस्व कर्मी हैं जो ग्राम प्रधान से ले कर जनता तो परेशान ही हैं तहसील के अधिकारी का भी हुक्म नहीं मानते दिख रहे, तहसील कोरांव की दशा ऊपर वाला ही मालिक है।

दरअसल तहसील कोरांव अंतर्गत ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति अलहवा में वर्ष 2021 से ही प्रदेश सरकार की तर्ज पर ग्राम समाज की जमीनों को भूमिफिया से विधिक कार्यवाही करते हुए खाली करा कर गरीब श्रमिकों भूमिहीनों को समाज

की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्राम प्रधान अहद अहमद सिद्दीकी उर्फ शहजादे पत्रकार कई बार एलएमसी के प्रस्ताव किए। किंतु लेखपाल जो समिति का सचिव होता है भू कब्जा कताओं के दबाव प्रभाव में कई बार बैठक का कोरम पूर्ण न होने का बहाना बताते रहे। किंतु किसी तरह छ माह पूर्व बैठक का कोरम पूर्ण होने में कामयाबी पाई।

इस बाबत ग्राम प्रधान ने एसडीएम तहसीलदार जिलाधिकारी से ले कर आयुक्त राजस्व विभाग लखनऊ तक पत्राचार किया किंतु सारी चिट्ठियां तहसील कोरांव में कर्मचारी डंप करते चले आए। मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी प्रयागराज ने एसडीएम कोरांव संदीप तिवारी को भी फोन से पत्र से व्हाट्सएप पर भी अलहवा के आवास एवं कृषि कार्य

हेतु पट्टे के लिए निर्देशित किया किंतु लेखपाल ने दस दिन के बहाने बता बता कर टालते आए और उनका यह कार्य है कि चुनाव तक टाल दें जिससे वर्तमान ग्राम प्रधान के कार्यकाल में न हो पाए आवंटन।

इस संदर्भ में एसडीएम कोरांव श्री तिवारी ने कहा जल्द आवंटन कर देंगे। कानूनगो भी थक हार गए। इसकी वजह यह निकल कर आई कि लेखपाल गैर तहसील के नहीं हैं जिस कारण स्थानीय होने के कारण संभवतः रिश्तेदारियों के दबाव और भू माफियाओं के प्रभाव में आवंटन नहीं करना चाहते।

इससे स्थिति यह है कि लोकल लेखपालों से एसडीएम या तहसीलदार आदि दबाव प्रभाव या डर में रहते हैं। जिस कारण उन्हें न तो गैर तहसील ट्रांसफर कर रहे और

न ही दंडित कर रहे। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जिले के डीएम सीआरओ एडीएम के आदेश पर भी एसडीएम लेखपाल से न तो पट्टे की पत्रावली तलब कर पाए और न ही भूमि प्रबंधक समिति चेयरमैन प्रधान को पट्टा की पत्रावली की प्रति लेखपाल दे सके।

फिलहाल ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी प्रयागराज से लिखित रूप से मांग किया कि अलहवा ग्राम सभा का आवंटन पत्रावली तलब कर पायें को आवंटन किया जाए अथवा ग्राम सभा अलहवा से उक्त लेखपाल को अन्यत्र हटा दिया जाए। तब आवंटन किया जाए। अन्यथा भू अतिचारी ग्राम समाज की जमीनों से न कब्जा छोड़ेंगे और न पट्टा करने देंगे। इस तरह जिलाधिकारी के हुक्म की नाफरमानियां हैं।

जारी गांव में तिपहिया वाहन पलटने से बुजुर्ग की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर



कौंधियारा। जारी गांव में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र के सन्ध कर दिया। रीवा रोड हाईवे पर जारी गल्ला मंडी के पास सुबह करीब 11 बजे एक तिपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में गांव के सम्मानित बुजुर्ग महेश प्रसाद द्विवेदी शास्त्री (72) की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन अचानक असंतुलित होकर पलट गया, जिसके नीचे शास्त्री जी दब गए। उन्हें तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर जैसे ही गांव पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में पत्नी, एक विवाहित बेटी

और दामाद ही उनकी जिम्मेदारी थे। शास्त्री जी गांव में अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय थे। शुरूआती दिनों में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और लंबे समय से कथा-वाचन, पूजन-कर्मकांड, विवाह संस्कार एवं धार्मिक कार्यक्रमों में सेवाएं दे रहे थे। उनके सरल स्वभाव, शांत आचरण और सेवा भावना के कारण गांव में उन्हें विशेष आदर प्राप्त था।

ग्रामीणों ने बताया कि पंडित जी हर किसी से अपनत्व से मिलते थे और समाज में सक्रिय सहभागिता रखते थे। दुर्घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में

ग्रामीण उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढाढस बंधाते रहे। रीवा रोड हाईवे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि तेज रफ्तार हादसे आम हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा उपायों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। अचानक हुए इस हादसे से जारी गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक की गहरी लहर दौड़ गई है।

सिलौधी में स्थापित हैंडपंप केवल जलस्रोत नहीं बल्कि हर घर की नई उम्मीद : अजय सिंह

मेजा ऊर्जा निगम ने नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत सिलौधी गांव के नईगढ़ी बस्ती में स्वच्छ पेयलाल हेतु स्थापित दो किया हैंडपंप, निगम की इस पहल की ग्रामीणों ने किया प्रशंसा

अखंड भारत संदेश

मेजा। सोमवार को मेजा ऊर्जा निगम (प्रा.) लिमिटेड द्वारा नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सिलौधी (नई गढ़ी) में 2 हैंडपम्प स्थापित किया गया। यह पहल पेयजल संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ग्रामीण समुदाय के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास भी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना प्रभावित एवं आस-पास के ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा स्थानीय निवासियों के जीवन में सुधार लाना है। स्वच्छ पानी की सुविधा प्राप्त होने से ग्रामीणों को न



सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि उनके दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन) श्री विवेक चन्द्र, अजय सिंह उप महाप्रबंधक मानव संसाधन, एवं जितेंद्र कसवाना, राजेश, ग्राम

प्रतिनिधि सिलौधी - नई गढ़ी, एवं त्रिभुवन नाथ पटेल ग्राम प्रधान हर्दिहा उपस्थित रहे। इस दौरान निगम के उप महाप्रबंधक अजय सिंह ने बताया कि कंपनी परियोजना प्रभावित एवं आस पास के ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता, स्वास्थ्य और

सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने ग्रामवासियों को इन सुविधाओं के संरक्षण और सामुदायिक सहयोग के महत्व से भी अवगत कराया। ग्राम सिलौधी में लंबे समय से स्वच्छ पेयजल की समस्या बनी हुई थी। लोग पोखरे से पानी पीने के लिए मजबूर थे। जैसे ही यह मुद्दा कंपनी के संज्ञान में आया, त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 72 घंटे के भीतर हैंडपम्प स्थापित कर स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। निगम की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर जनजीवन को गहराई से प्रभावित करेगी और बच्चों के

स्वास्थ्य में सुधार होगा। महिलाओं का रोजाना दूर-दूर से पानी लाने में लगने वाला समय बचेंगा और परिवारों को सुरक्षित व स्वच्छ जल तक सहज पहुंच मिल सकेगी। सिलौधी गांव में स्थापित ये हैंडपम्प केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि हर घर की नई उम्मीद हैं। यह एक ऐसा भरोसा है जो हर सुबह ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाता है कि स्वच्छ पानी अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है, न कि एक चिंता। ग्रामवासियों ने मेजा ऊर्जा निगम द्वारा पेयजल के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा निभाया जा रहा नैगम सामाजिक दायित्व वास्तव में समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व दीवाल घड़ी देकर किया सम्मानित

अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ, अन्य बीएलओ को भी मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत शीघ्रता से पूर्ण किये जाने हेतु प्रेरित करें : जिलाधिकारी

अखंड भारत संदेश

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को संपन्न सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व दीवाल घड़ी देकर सम्मानित किया। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ से कहा कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। कहा कि आप अपने साथ इस कार्य में लगे हुए अन्य भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मानित होने वाले बीएलओ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 254-



करें। जिलाधिकारी ने बीएलओ के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मानित होने वाले बीएलओ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 254-

काफामऊ की पुष्पलता श्रीवास्तव, छाया मिश्रा, रीता देवी यादव, कृष्ण कुमार, 255-सोरांव की आलिया बानो, सुनीता देवी, 256-फूलपुर के राम सजीवन यादव, 257-प्रतापपुर की गीता देवी, विद्या देवी मौर्य, 258-

हण्डिया के सौरभ सिंह, 259-मेजा के रवि शंकर यादव, 260-करछना के श्याम बाबू, 261-इलाहाबाद पश्चिम के सत्य प्रकाश खरवार, जरीना खातून, अमर बहादुर सिंह 264-बारा के सूर्यराज सिंह, संतोष कुमार एवं

265-कोरांव के अरविन्द कुमार एवं कृष्णकान्त है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पूजा मिश्रा सहित निर्वाचन से सम्बंधित अन्य अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहे।

अखंड भारत संदेश

नैनी। नैनी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय श्रीवास्तव, काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह के नेतृत्व में आज शिवनगर, नंदन तालाब, कृष्णा नगर में घूम-घूम कर सभी के दरवाजे पर जाकर जागरूक करते रहे बच्चों को साथ में लेकर जन जागरण रैली निकाली गई जन जागरण अभियान के अंतर्गत सभी मतदाता बंधुओं से अपना एसआईआर फॉर्म को भरकर पतविंदर सिंह काशी प्रांत उपाध्यक्ष जिससे आप लोगों का मतदाता सूची से नाम ना काटे और सभी लोगों का नाम आ जाए मतदान करना हम सभी का परम कर्तव्य है मतदान से ही लोकतांत्रिक सरकार बनती है। जो देश के हित में समाज के हित में किसानों के हित में व्यापारियों के हित



में सुचारु रूप से चुनकर के जाते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। आप सभी लोगों से अपील करते हुए सरदार पतविंदर सिंह काशी प्रांत उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा कि सम्मानित नागरिकों आप सब लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आपका वोट सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपकी आवाज, आपकी पहचान और आपके अधिकार की गारंटी है। सही वोट को परखने के लिए एसआईआर है जरूरी।

कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय श्रीवास्तव ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर फॉर्म भरवाने का निवेदन किया। इस अवसर पर बच्चों के साथ-साथ पार्षद मयंक यादव, सेक्टर प्रभारी प्रदीप तिवारी, नैनी मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा, महामंत्री उमेश सेन, सनी, पिपूष, अमन, प्रिया, मनु पांडे, वर्तिका, अंश सहित दर्जनों बच्चे रहे साथ पूरे मोहल्ले में जन जागरण अभियान चलाया गया।

कौशाम्बी संदेश

50 हजार कीमत का खोवा को फूड इंस्पेक्टर ने कराया नष्ट

अखंड भारत संदेश

कौशांबी। चरवा थाना क्षेत्र के चरवा चौराहा में इलाके के किसान पशुपालकों द्वारा खोवा बेचने का लगातार व्यापार किया जाता है इन पशुपालकों से फूड इंस्पेक्टर को महीने की रकम नहीं मिलती है जिससे पशुपालकों के ऊपर हमेशा फूड इंस्पेक्टर नाराज रहते है और जब मौका मिला तो पशुपालक को मिलावटी खोवा बता करके फूड इंस्पेक्टर नष्ट करवा देते हैं जिससे पशुपालकों को बड़ा झटका लगता है फूड इंस्पेक्टर का इस कदर आतंक है कि चरवा बाजार में जब फूड इंस्पेक्टर की टीम जांच करने पहुंची तो पशुपालन मौके से घटने को मजबूर हो गए लगभग दो कुंटल खोवा मौके पर फूड इंस्पेक्टर को मिला जिसे नकली बतायात हुए फूड इंस्पेक्टर ने नष्ट कर दिया है जिस खोवा को फूड इंस्पेक्टर ने नष्ट

पनीर खोवा की बड़ी फैक्ट्री बड़े दुकानदारों पर फूड इंस्पेक्टर हमेशा रहे मेहरबान, दो-चार किलो खोवा लाने वाले पशुपालकों से महीने की रकम चाहते हैं विभाग के लोग



किया है क्या उसका नकली होने का संपल फूड इंस्पेक्टर के पास प्रमाण मौजूद है चरवा चौराहा में कई वर्षों से खोवा मंडी से पूरे जिले के लोग इलाके के सैकड़ो पशुपालक घर में

खोवा बनाकर बाजार में बेचते हैं उन्हें फूड इंस्पेक्टर माफिया बताते हैं इन्हें शर्म नहींआती है चरवा चौराहे की खोवा मंडी से पूरे जिले के लोग शादी विवाह कार्यक्रम में खोवा

खरीद कर ले जाते हैं पूरे जिले के लोगों को चरवा चौराहे के खोवा पर भरोसा है फूड इंस्पेक्टर की वसूली के दबाव के आतंक से यदि चरवा की खोवा मंडी बंद हो जाएगी तो लोगों के घरों में शादी विवाह कार्यक्रम में खोवा मिलना मुश्किल हो जाएगा। प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से आने वाले खोवा की शुद्धता की गारंटी नहीं है बड़े शहर के दुकानों में मिलने वाले खोवा के नाम पर न जाने कितने केमिकल और अन्य चीज मिलाकर खोवा बेचा जा रहा है लेकिन बड़े दुकान बड़ी फैक्ट्रीयों पर फूड इंस्पेक्टर का चाबुक नहीं चलता पशुपालको पर ही उनका पूरा कानून चल रहा है सूत्रों की माने तो विभिन्न योजनाओं से करोड़ों की वसूली होती है फूड इंस्पेक्टर भारत मिश्रा की मौजूदगी में चरवा चौराहे पर खोवा को गड़्डे में दफन कर दिया गया चरवा चौराहा पर खोवा लाने वाले पशुपालक चार

पांच किलो खोवा लेकर आते हैं कुछ पशुपालक तो दो किलो ही खोवा लेकर बाजार में आ जाते हैं और दो-चार किलो खोवा लाने वाले पशुपालकों से महीने की रकम विभाग के लोग चाहते हैं लेकिन जिले में कई बड़ी फैक्ट्री कई बड़े दुकानों में पनीर और खोवा की फैक्ट्री संचालित हो रही है जहां लाखों रुपया रोज का पनीर खोवा मिलावटी बेचा जाता है जिसकी पूरे जिले में चर्चा होती है राजस्थान के कई लोगों ने जिले में दुकान फैक्ट्री डल लिया है खुलेआम पाउडर से खोवा पनीर बनाते हैं लेकिन महीना मिलने के चलते उनके पूरे गुनाह माफ है सूत्रों की माने तो राजस्थान के मामले का खुलासा फूड इंस्पेक्टर करेंगे या फिर इसी तरह पशुपालकों का शोषण कर वह कानून का हवाला दें कर बड़े अधिकारियों को गुमराह कर वाहवाही लूटते रहेंगे।

छापा पड़ा तो मिलावट खोरी का खुलासा हुआ लेकिन राजस्थानियों की फैक्ट्री से मोटा महीना मिलता है जिससे इन घूसखोर अफसरों को डकार भी नहीं आती है खोवा पनीर की बड़ी फैक्ट्री पर फूड इंस्पेक्टर का छापा नहीं पड़ता है उन पर मेहरबानी बनी रहती है और गरीब पशुपालकों के खोवा को मिलावटी बता करके उसे नष्ट कर करके पशुपालकों पर फूड इंस्पेक्टर दबाव बनाकर अपनी महीना की वसूली की रकम बांधने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरी व्यवस्था पर सवाल है क्या राजस्थान के लोगों द्वारा आधा दर्जन से अधिक संचालित फैक्ट्री में पाउडर से खोवा पनीर बनाए जाने के मामले का खुलासा फूड इंस्पेक्टर करेंगे या फिर इसी तरह पशुपालकों का शोषण कर वह कानून का हवाला दें कर बड़े अधिकारियों को गुमराह कर वाहवाही लूटते रहेंगे।



जिलाधिकारी ने की सोशल सेक्टर की समीक्षा बैठक

कौशांबी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में उदयन सभागार में सोशल सेक्टर की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिलाधिकारी ने छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रधानाचार्यों/ प्रबन्धकों के साथ समन्वय कर आवेदनों का सत्यापन आदि कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि आवेदनों को समय-सीमा के अन्दर निस्तारित किया जाय। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु के दृष्टिगत वृद्धाश्रम में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करा लिया जाय। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजकीय आश्रम पध्दति विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थायें/ कार्यवाही सुनिश्चित बनाये रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ओ-लेवल एवं ट्रिपल-सी कोर्स की समीक्षा के दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अधिवक्ता पर जानलेवा हमला के विरोध में वकीलों ने किया प्रदर्शन

पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग

अखंड भारत संदेश

कौशांबी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू में रविवार रात्रि को अधिवक्ता अनंत कुमार पांडे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और लूटपाट भी हुई। हमले में अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए अधिवक्ता पर हमले की जानकारी जैसे ही मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक पहुंची अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और घरना प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ता अनंत कुमार पांडे रविवार रात करीब 8 बजे एक निमंत्रण से वापस लौट रहे थे, तभी सिराथू नगर पंचायत के टाकीज रोड पर भानु प्रताप पुत्र प्रेमलाल निवासी सिराथू थाना-सैनी और 6-7 अन्य लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास लोहे की रॉड, लाठी, डंडे, बेल्ट और अन्य हथियार थे। उन्होंने जान से मारने की नीयत से मारपीट की और फवारिग भी की हमलावरों ने अधिवक्ता पांडे की जेब से पैन कार्ड,आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और 1600 रुपये नकद छीन लिए। पीड़ित अधिवक्ता ने उसी रात सैनी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि थाना पुलिस द्वारा



कोई कार्रवाई न होने से नाराज मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कौशांबी के अधिवक्ताओं ने सोमवार को लाइब्रेरी हॉल में बैठक की। संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे एडवोकेट की अध्यक्षता में बैठक हुई इस बैठक में घटना की निंदा की गई इसके बाद, मॉडल बार एसोसिएशन के

अधिवक्ताओं ने एसपी कौशांबी से मुलाकात की और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। मॉडल बार एसोसिएशन के महामंत्री तुषार तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने सैनी कोतवाली को मामले में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

राजा भैया चाहते हैं कि समाज का हर गरीब कमजोर तबका तरक्की करें : पूर्व सांसद

अखंड भारत संदेश

भरवारी कौशांबी। जनसत्ता दल पार्टी का 7 वां स्थापना दिवस जनपद मुख्यालय मंझनपुर कार्यालय में सोमवार को बहुत ही धूम धाम से मनाया गया इस मौके पर जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं पूर्व सांसद शैलेन्द्र कुमार ने पार्टी की नीति और सिद्धांतों के बारे में लोगों को बताते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि संगठन दबे कुचले मजलूम कमजोर लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़ा दिखाई पड़ेगा उन्होंने कहा कि कुंडा के राजा खुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मजलूम कमजोर गरीब दबे कुचले लोगों के सहयोग और उत्थान की भावना से जनसत्ता दल पार्टी का गठन किया है राजा भैया चाहते हैं कि समाज का हर गरीब कमजोर तबका तरक्की करे। बैठक के दौरान किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर सिंह युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष अश्वनी सिंह पूर्व विधान



सभा प्रत्याशी अनिल केशरवानी डॉ पोंके सिंह राजू सिंह रामू अग्रहरि जनसत्ता दल पार्टी की नीति और सिद्धांत के बारे में लोगों को अवगत कराया और जनसत्ता दल पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में पार्टी की स्थापना दिवस में केक काटकर बहुत ही धूम धाम से जनसत्ता दल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया इसी बीच तमाम लोगों ने पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए जनसत्ता दल

पार्टी में शामिल हुए इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भविष्य में एक राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टी से गठबंधन होने की प्रबल संभावना को देखते हुए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक जुट होकर पार्टी का चुनाव प्रचार में अभी से ही जुट जाने का सुझाव दिया ' पार्टी का नेतृत्व जनसत्ता दल कौशांबी के जिला अध्यक्ष इरफान अहमद ने किया तथा आए हुए सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

गोवध करने वाले 02 अभियुक्त मुहमेड़ में घायल कुल 3 गिरफ्तार

अखंड भारत संदेश

कौशांबी। करारी थाना क्षेत्र के ग्राम तियरा जमालपुर में गौकशी की जानकारी के बाद हिंदू संगठन ने विरोध प्रकट किया पुलिस मौके पर पहुंची गोवंश के अवशेष हड्डी आदि संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए मिले करारी पुलिस ने अवशेषों के सेमुल परीक्षण हेतु एकत्रित किए तथा इस संबंध में थाना करारी पर मु0ओसं0-387/2025 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत हुआ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा घटना की गम्भीरता को देखते हुए घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर निर्देशित किया गया। गठित टीमों द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्पादित स्थानों पर दबिश देकर तलाश की जा रही थी। इसी दौरान थाना करारी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त गौकशी की घटना के अभियुक्त हिसामपुर नहर पुलिया के पास मौजूद है तथा पुनः ऐसी घटना को करने तथा अवशेषों को छुपाने की



फिराक में है सूचना के आधार पर करारी थाना पुलिस ने मंझनपुर कोतवाली पुलिस के साथ उनको पकड़ने के लिए जैसे ही मौके पर पहुंची तो उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया पुलिस टीम ने आत्म समर्पण हेतु कहा तो उन्होंने भागते हुए पुनः पुलिस टीम के ऊपर फायर किया पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए फायर किया जिसमें 02 अभियुक्तों के पैर में गोली लग गई तथा एक अन्य अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा उसे भी पुलिस टीम द्वारा घेरावदी कर-

के गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों से पृष्ठताछ करने पर उन्होंने अपने नाम तुफैल अहमद पुत्र मोहम्मद महबूब निवासी बहादुरपुर थाना मंझनपुर वा मुन्ना पुत्र रहमत अली पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया तथा गिरफ्तार तीसरे अभियुक्त द्वारा अपना नाम नयाब पुत्र मोहम्मद अतहर निवासी बहादुरपुर थाना मंझनपुर बताया गया घायल अभियुक्तों को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा गया मौके से 02 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस, 04 खोखा कारतूस बरामद हुआ।

राष्ट्रपति के कार्यक्रम में धर्मा देवी इंटर कॉलेज केन के छात्रों ने जलवा बिखेरा

अखंड भारत संदेश

कौशांबी। 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी, लखनऊ में 23 नवम्बर 2025 से 29 नवम्बर 2025 के मध्य विकसित युवा-विकसित भारत व एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर आयोजित हुए भारत स्काउट व गाइड कार्यक्रम में प्रतिभाग कर विद्यालय वापस लौटे धर्मा देवी इण्टर कॉलेज के 07 छात्रों के साथ स्काउट मास्टर ललित कुमार का 01 दिसम्बर 2025 को प्रार्थना सभा में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. राम किरण त्रिपाठी व अन्य शिक्षकों द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्काउट मास्टर ललित कुमार ने प्रार्थना सभा में विद्यालय के बच्चों को इस हीटक जयंती कार्यक्रम की गतिविधियों के विषय में जानकारी दी गई इस कार्यक्रम का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश

भारत स्काउट गाइड कार्यक्रम में प्रतिभाग कर विद्यालय वापस लौटे विद्यार्थी और शिक्षक का हुआ सम्मान



की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने किया था। इस कार्यक्रम में छात्रों ने पाइनारिंग, कैम्पक्राफ्ट, एडवेंचर, नाटक, लोकनृत्य व फूडरलाजा आदि विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग

कर कौशाम्बी जनपद के साथ साथ प्रयागराज मण्डल को गौरवान्वित किया। कार्यक्रम का समापन नारी शक्ति की प्रतिरूप भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया।

महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में पांच दिवसीय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन



नंदिनी द्वितीय स्थान सुनीता तृतीय स्थान बालिका सीनियर वर्ग प्रिया विश्वाकर्मा प्रथम स्थान आचल यादव द्वितीय स्थान प्रतिभा तृतीय स्थान वा दो सौ वर्ग मीटर दौड़ प्रतियोगिता जूनियर बालिका वर्ग सोमन पुत्री रोशन लाल प्रथम स्थान नंदनी पुत्री लालमनी यादव द्वितीय स्थान खुशी पुत्री प्रेमचंद तृतीय स्थान सुनील तृतीय स्थान सीनियर बालक वर्ग दो सौ मीटर दौड़ हिमांशु कुमार पुत्र भारत लाल प्रथम स्थान पुष्पेंद्र पुत्र दशरथ द्वितीय स्थान रंजन पुत्र भारत लाल तृतीय स्थान दो सौ वर्ग

मीटर दौड़ प्रतियोगिता जूनियर बालिका वर्ग सोमन पुत्री रोशन लाल प्रथम स्थान नंदनी पुत्री लालमनी यादव द्वितीय स्थान खुशी पुत्री प्रेमचंद तृतीय स्थान सुनील तृतीय स्थान सीनियर बालक वर्ग दो सौ मीटर दौड़ प्रतियोगिता प्रिया विश्वाकर्मा पुत्री गुरेलाल प्रथम स्थान प्रतिभा पुत्री करन सिंह द्वितीय स्थान मोहिनी पुत्री जय सिंह तृतीय स्थान वा जूनियर बालक वर्ग सौ मीटर दौड़ प्रतियोगिता संदीप प्रथम स्थान शैलेंद्र कुमार द्वितीय

लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण के डीएम ने दिए निर्देश

कौशांबी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने आज उदयन सभागार में बाल कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की जिलाधिकारी ने अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति को लम्बित प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने परिवार में भेजे गये एवं संस्थानों में रह रहें बच्चों का नियमानुसार फॉलो-अप करने के भी निर्देश दिए।(जिलाधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी को लम्बित प्रकरणों में शीघ्र बैंक खाता खुलवाने के निर्देश दिए हुए कहा कि सभी कार्यवाही समयबद्ध किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी शिकायत लम्बित न रहने पाये।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

शादी विवाह में फायरिंग करने वाले असलहे समेत दो गिरफ्तार

कौशांबी। चरवा थाना क्षेत्र के सीरियावा कला गांव में 2 दिन पहले शादी विवाह में फायरिंग करने वाले मोहम्मद साजिद ग्राम प्रधान पुत्र मोहम्मद कासिम वा नसीम पुत्र मोहम्मद हालिम साहबे आलम मो.हकीम राणा समशुल, बिट्टु मुन्तजिगर, आकिद समेत 10 अज्ञात लोगों पर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और रविवार की शाम पुलिस ने एक राइफल वा एक बंदूक के साथ मोहम्मद साजिद और मोहम्मद हकीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया है अभी तमाम आरोपी फरार है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी भारी मात्रा मे खोखा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है।

वारण्टी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कौशांबी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के निरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में थाना पश्चिम शरीरा पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित अ0स0अ 69/02 धारा 323/324/325/504 भादवि द्वारा पश्चिम शरीरा से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राजाराम प्रजापति पुत्र रामसेर निवासी गढ़ी बाजार थाना पश्चिम शरीरा को गिरफ्तार किया गया विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया।

तिल्हापुर मोड़ **कौशाम्बी।** समाज वादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष निसार अहमद सिद्दीकी ने समाज वादी पार्टी को छोड़कर सैकड़ो समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है अनिल कुमार गौतम प्रदेश संगठन मंत्री ने डॉक्टर निसार अहमद सिद्दीकी को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी स्थापन कराया है इस कार्यक्रम में तनवीरुल हसन जिला अध्यक्ष, ओमकर लहरी जिला महामंत्री, अरविंद मौर्य जिला संगठन मंत्री,राज खेमा जिला प्रभारी तनवीर अंसारी महानगर अध्यक्ष प्रयागराज आदि लोग उपस्थित रहे डॉ निसार अहमद के समाजवादी पार्टी छोड़ दिए जाने के बाद सपा कोई बड़ा झटका लगा है जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सपा को भुगतना पड़ सकता है।

सम्पादकीय

अच्छी परंपराओं की सीख

हमें पुरानी अच्छी परंपराओं से सीख लेनी चाहिए। चाहे हमारे बुजुर्ग हों, पुरखे हो, गांधी हो, बुद्ध हो, वे बाहर कितानों में नहीं हैं। अगर हमें उनकी कोई चीज, व्यवहार व आदतें अच्छी लगती हैं, तो उन्हें अपनाना चाहिए। कोई भी अच्छा विचार, परंपरा कहने की चीज नहीं है, बरतने की चीज हैं। सर्दियों का मौसम आ गया है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। रंग-बिरंगी स्वेटर, शॉल, ऊनी टोपी, जैकेट, मफलर इत्यादि की दुकानें सजने लगी हैं। लेकिन मैं आज ऐसी परंपराओं की चर्चा करना चाहूँगा, जो चीजों को संभालकर बरतने की थी। उनसे यादें तो जुड़ी ही होती थीं, साथ ही कचरा भी नहीं होता था।

अगर मैं अपने बचपन को याद करूँ तो हमारे घर सर्दियों के दिनों में हम धान के पुआल का बिछौना बनाकर सोते थे। यह बहुत ही गर्म होता है और सोने में बहुत आरामदायक होता था और ठंड से बचाव के लिए रात में गुदड़ी ओढ़कर सोते थे। मेरी मां, जिसे मैं बाई कहता था, फटे-पुराने कपड़ों से गुदड़ी बनाती थी। फुरसत के समय वह पुराने कपड़ों को काटकर, सुई धागे से सिलकर गुदड़ी सिलती रहती थी। बाजार से सामान लाने के लिए झोले व तकिया का खोल बनाती थी। हमारे फटे हुए कपड़ों को सिलती थीं, कई बार तो उनमें पैबंद भी लगती थीं, जिससे कपड़ा मजबूत व पहनने लायक हो जाए।

इस तरह की परंपराएं देशभर में दिखने को मिलती हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में गुजरात के कच्छ इलाके में था। वहां के पशुपालक मालधारी हैं। वहां की महिलाएं बहुत ही सुंदर गुदड़ी बनाती हैं। खाली समय में महिलाएं यह काम करती रहती हैं। उन्होंने गुदड़ी एक मित्र को भेंट में भी दी थी। हमारे स्कूल के दिनों में लोग चिट्ठी लिखते थे। गांधी और नेहरू की चिट्ठियों को तो प्रसिद्ध ही हैं। उस समय कलम दवात वाली कलम से चिट्ठी लिखी जाती थी। हम सबने इसी पेन से लिखा है। अगर पेन की निब घिस जाती थी, तो बदल लेते थे। यह पेन सस्ता होता था, और लम्बे समय तक इस्तेमाल किया जाता था। इस पेन से अक्षर भी अच्छे बनते थे, लिपि भी सुधरती थी। अब यह निब वाला पेन दिखाई नहीं देता है। दुकानों पर भी मुश्किल से मिलता है।

इसकी जगह रफ़िल वाला पेन आ गया है। रफ़िल और प्लास्टिक की पूरी बाँड़ी। दोनों ही कचरा पैदा करते हैं। घर से निकलने वाले कचरे में यह भी शामिल हो गया है। कई शहरों में कभी-कभार प्लास्टिक की थैलियां प्रतिबंधित है, पर रफिल वाले पेन तो चल रहे हैं। यह भी तो कचरा फैलाने का काम करते हैं। कम्प्यूटर व मोबाइल पर भी कुछ लोग लिखने लगे हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम है। जैसे-जैसे शिक्षा का दायरा बढ़ता जाएगा, कलम की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। इसी अनुपात में कचरा भी बढ़ता जाएगा। मध्यप्रदेश के हमारे एक मित्र पुराने लिफाफे, एक तरफ लिखे कागजों का इस्तेमाल करते थे। वह अच्छी सोच है। इस संदर्भ में मैं ऐसे दो लोगों को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने पुरानी चीजों और कबाड़ को शिक्षा का माध्यम बनाया। इनमें से एक हैं इन्दौर (मध्यप्रदेश) के कलागुरु विष्णु चिंचालकर और दूसरे हैं पुणे के अरविंद गुप्ता। विष्णु चिंचालकर, जिन्हें गुरूजी कहा जाता था, ने बेकार मानी जानी वाली चीजों से बेजोड़ कलाकृतियां बनाईं। उनकी कला की दुनिया रंगों व ब्रश के दायरे से बड़ी थी। वे घास के तिनकों, सूखे पत्ते, टहनी, पत्थर, घर में पड़ी बेकार चीजों को नया रूप दे देते थे।

●●●●●

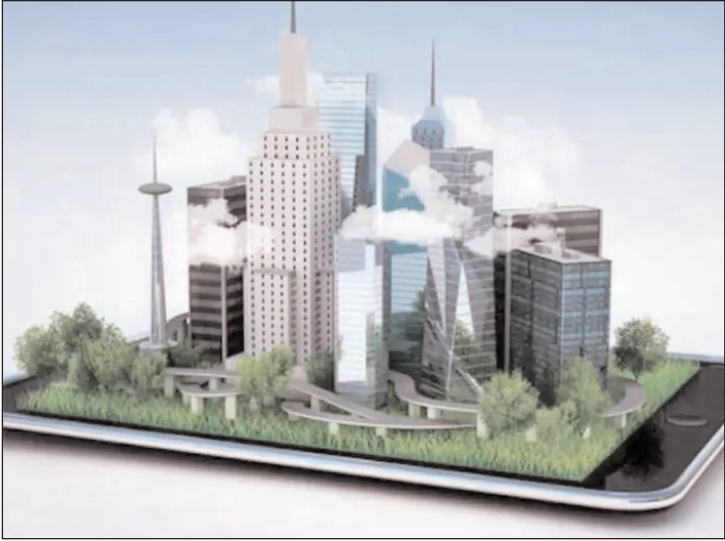
'स्मार्ट सिटी' में डाटा : निजीकरण से कमाई?

खालिक पारकर
'स्मार्ट सिटीज मिशन' और 'इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज' ने शहरी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में ये इस बात की याद दिलाते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग हमारे डेटा के वस्तुकरण और निजीकरण को तेज करने के लिए किया गया है। भारतीयों को इस मूल धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए स्मार्ट सिटीज मिशन' ने डेटा-आधारित शासन के एक नए दौर की शुरुआत कर-के भारत के शहरों को पुनर्जीवित करने का वादा किया था। इसमें कहा गया था कि ऐप्स के जरिए डेटा का उपयोग कर-के नागरिकों को प्रमाणपत्र और अधिकारिक दस्तावेज सिधे उपलब्ध कराए जा सकेंगे, जबकि संपत्तिकर और सेवाओं के बिलों की ऑनलाइन वसूली से नगर निगमों की आमदनी में सुधार किया जा सकता है। इसने यह विचार भी रखा कि शहरी सेवाएं जैसे सार्वजनिक परिवहन, यातायात नियंत्रण और कचरा संग्रहण, डेटा विश्लेषण और स्वचालन के उपयोग से काफी बेहतर बनाई जा सकती हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल और सूरत जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन, यातायात और कुछ मामलों में ठोस कचरे से जुड़ा डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न सेंसर, नेटवर्क और डाटाबेस स्थापित किए गए। मिशन के तहत चुने गए सौ शहरों में बनाए गए 'इटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों' के प्लेटफॉर्म इन डिजिटल संरचनाओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके शहरी सेवाओं को स्वचालित करने वाले थे। डेटा डैशबोर्ड डिश प्रशासन को प्रदर्शन की निगरानी में मदद करने के लिए बनाए गए थे, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इन डेटा आधारित प्रयासों को दिशा देने के लिए 'डेटा स्मार्ट सिटीज स्ट्रैटेजी' जारी की थी। इसके अलावा, 'इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज' नामक एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म ने 'स्मार्ट सिटीज मिशन' के तहत 50 शहरों की डिजिटल अवसंरचना

से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित किया, लेकिन दस साल बाद भी 'स्मार्ट सिटीज मिशन' के वादे पूरे नहीं हुए हैं। इसके बजाय, इन आकर्षक नारों के पीछे सार्वजनिक धन से तैयार की गई अवसंरचना और डेटा का उपयोग शहरी शासन के निजीकरण को तेज करने के लिए किया जा रहा है। 'स्मार्ट सिटीज मिशन' की कमियों के बावजूद, डेटा आधारित शासन और ऐप्स नए शहरी कार्यक्रमों का केंद्र बने हुए हैं। साल 2021 में 'नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन' ने पूरे देश के सभी शहरों और कस्बों में नागरिकों को प्रमाणपत्र और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'उपयोग' नामक एक एकीकृत ऐप पेश किया। इस वर्ष 'ट्रांसपोर्ट स्टैक' परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनके तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए ऐप्स लाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य ऑनलाइन टिकटिंग, मार्ग योजना और वाहनों की ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शहरी डिजिटल डेटा तैयार करने का प्रयास नयश्चा नहीं है। पिछले चार दशकों में भूमि स्वामित्व शीर्षक, संपत्तिकर, रजिस्टर और जन्म-मृत्यु पंजीकरण जैसे नगर निगम अभिलेखों को धीरे-धीरे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत डिजटाइज किया गया। साल 2006 की 'नेशनल ई-गवर्नेंस योजना' ने इन प्रयासों को कुछ गति दी थी, लेकिन अधिकांश राज्यों ने नागरिकों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और शहरों के संपत्ति रिकार्ड का एकीकरण केवल करके शहरी सेवाओं को स्वचालित करने वाले थे। डेटा डैशबोर्ड डिश प्रशासन को प्रदर्शन की निगरानी में मदद करने के लिए बनाए गए थे, ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सके।

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने इन डेटा आधारित प्रयासों को दिशा देने के लिए 'डेटा स्मार्ट सिटीज स्ट्रैटेजी' जारी की थी। इसके अलावा, 'इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज' नामक एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म ने 'स्मार्ट सिटीज मिशन' के तहत 50 शहरों की डिजिटल अवसंरचना



लगाने, सार्वजनिक परिवहन वाहनों की निगरानी करने और कचरा संग्रहण को मापने के लिए डिजिटल अवसंरचना स्थापित की। 'इटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' में मौजूद साफ्टवेयर का उद्देश्य इन आंकड़ों का विश्लेषण कर शहरी सेवाओं में सुधार करना था— जैसे स्वचालित सिग्नलों के जरिए यातायात नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन की पहुंच और प्रदर्शन की निगरानी, तथा 'प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स' के माध्यम से बेहतर आवागमन और कचरा संग्रहण मार्ग सुझाना। यातायात उल्लंघन सेंसर, नंबर प्लेट पहचान कैमरे और सभी पंजीकृत वाहनों के केंद्रीय वाहन डेटाबेस के माध्यम से जुमानें की वसूली में तो वृद्धि हुई है, लेकिन 'स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली' अक्सर व्यस्त घंटों में अपने निर्धारित तरीके से काम नहीं करती। सार्वजनिक परिवहन तक बेहतर पहुंच के सबूत बहुत कम हैं, क्योंकि 'स्मार्ट सिटीज मिशन' के ऐप वाहन की वास्तविक स्थिति की जानकारी देने में विफल रहे। डेटा के उपयोग से कचरा संग्रहण या मार्ग योजना में सुधार का भी कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं है। शहरों में अपातकालीन वाहनों के लिए 'ग्रीन कॉरिडोर' बनाने की कई पायलट

'समाधान' के रूप में बेचा गया। इसी तरह के ऐप यातायात नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सूरत, बेंगलुरु और वाराणसी जैसे शहरों में भी लागू किए गए।

प्रमाणपत्र, लाइसेंस और बिलिंग की डिजिटल डिलीवरी डिजिटलीकरण के पूरा होने के बाद निश्चित रूप से तेज और अधिक कुशल हुई है, लेकिन यह वास्तव में 'स्मार्ट सिटीज मिशन' की नहीं, बल्कि पहले की ई-गवर्नेंस सुधार पहलों की क्रमिक सफलता है। 'स्मार्ट सिटीज मिशन' ने केवल इन सेवाओं तक पहुंच के लिए एकीकृत ऐप्स पेश करके इन पहलों को पूरा करने में सहायता की। इस क्षेत्र में 'स्मार्ट सिटीज मिशन' का योगदान सार्वजनिक धन से डिजिटल अवसंरचना स्थापित करने तक सीमित रहा। जो जानकारी एजेंसियों को शहरी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद करने के लिए एकत्र की गई थी, वह अंततः 'इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज' के माध्यम से एक वस्तु में बदल गई। इन ऐप्स को विकसित और बढ़ावा देने वाले उद्योग प्रतिनिधियों का दावा है कि ये नागरिकों और शहरी सेवाओं में सुधार से जुड़ी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करेंगे। हालांकि मंत्रालय और उद्योग जगत इन ऐप्स को 'डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' कह रहे हैं, लेकिन इनका एकमात्र 'सार्वजनिक' पहलू वह डेटा है जिस पर ये निर्भर करते हैं— और यह डेटा दशकों से सरकार द्वारा वित्तपोषित डिजिटल परियोजनाओं और अवसंरचनाओं से प्राप्त हुआ है।

'स्मार्ट सिटीज मिशन' और 'इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज' ने शहरी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में ये इस बात की याद दिलाते हैं कि सार्वजनिक धन का उपयोग हमारे डेटा के वस्तुकरण और निजीकरण को तेज करने के लिए किया गया है। भारतीयों को इस मूल धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए डेटा आधारित शासन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना हमारे शहरों को बेहतर बनाने की आदर्श रणनीतियां हैं।

केंद्र की श्रम संहिताएं करती हैं

मजदूरों की सुरक्षा को कमजोर



नीलोत्पल बसु
कोई प्रौद्योगिकी को उत्पादन की प्रक्रिया में एक जरूरी चीज मानता है, तो आज इसका इस्तेमाल सिर्फ 'पूंजी के साथ हो रहा है। एक तरफ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कामगारों को बराबर सुरक्षा न मिलने से शोषण जरूर बढ़ेगा। लेबर कोड का हर नियम इसी तरफ इशारा करता है।

हार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बड़ी चुनौती जीत और उसके साथ हुई खुशी के तुरंत बाद भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को अधिसूचित कर दिया है। मजदूरी, औद्योगिक संबंध, काम से जुड़ी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बनी ये संहिताएं देश के '29 श्रम कानूनों को आसान बनाने' के नाम पर हावी हो गई हैं। सच तो यह है कि ये लेबर कोड उन कानूनों में शामिल मजदूरों की सुरक्षा के निशानों को कमजोर करते हैं और नष्टा देते हैं। नौकरी की सुरक्षा के सवाल पर, श्रम विभाग की सभी संभावित भूमिकाएं खत्म कर दी जाएंगी। समंतिष्ठ क्षेत्र में काम करने वाले 90प्रतिशत कार्यबल को सभी सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास नियुक्ति का अधिकार (अर्पाइंटमेंट अथॉरिटी) नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि लेबर कोड सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी पक्का करेगा। लेकिन, कई राज्यों की मौजूदा न्यूनतम मजदूरी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और स्कीम वर्कर्स समेत लाखों कामगार न्यूनतम मजदूरी से बाहर हो जाएंगे, न्यायपूर्ण (फेयर) या लिविंग वेज(जीव चलाने के लिए जरूरी मजदूरी) की तो बात ही छोड़ दें।

यह भी दावा किया जा रहा है कि लेबर कोड्सुगिंग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाएंगे। लेकिन, इसके लिए कोई फंड देने या कोई समवर्षीमा नहीं है। लेकिन नियोक्ता-कामगार संबंध का कई ड्रिफ्ट के बिना, आधार आधारित व्यवस्था वर्तमान कार्यबल के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करेगा? एक और दावा यह है कि नये लेबर कोड के अनुसार 'निश्चित समय के लिए रोजगार' से बराबर फायदे पक्के होंगे। सच तो यह है कि यह सिर्फ स्थायी और कोर

जॉब्स में स्थायी रूप से अस्थायी स्थिति लाएगा, और सभी स्थायी नौकरियों को अल्पावधि ठेके वाले कार्य से बदल देगा। इससे सर्विस की निरंतरता, वरीयता और असली फायदों का नुकसान होगा और इसके नतीजे में यूनियन कमजोर होंगी।लेबर कोड सरकार को कंप्लायंस के रक्षक और नियामक की भूमिका से हटाते हैं, शिकायत आधारित निरीक्षण की प्रणाली को ही खत्म कर देते हैं और उसकी जगह स्व-प्रमाणिकरण लाते हैं, जो नौकरी करने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी मौजूदा प्रावधानों को तोड़ने की आजादी का एक नरम शब्द है। एक दावा यह है कि नये लेबर कोड से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), वृक्षारोपण, खनन और विनिर्माण कामगारों की सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। यह सच से कोसों दूर है।एमएसएमई के कामगार इस कोड के प्रावधानों दायरे से बाहर हैं और सेस उगाही में पारदर्शिता की कोई प्रणाली नहीं है। खनन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों जिनमें दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती हैं, में निरीक्षण कम करने से सिर्फ और ज्यादा जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं और नियोक्ताओं की जिम्मेदारी आपराधिकता से मुक्त हो जाएगी। केंद्र सरकार अपने प्रेस बयान और प्रोशल मीडिया पर जोर-शोर से कह रही है कि उन्होंने श्रम कानूनों को लेबर कोड से बदलने के लिए कामगारों के साथ हर मुमकिन विचार-विमर्श किया है। आजाद भारत में 1966 में बने पहले नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच तीन-तरफा विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (आईएलसी) आयोजित करने की

●●●●●

श्रीराम मन्दिर ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की बौखलाहट

-ललित गर्ग-

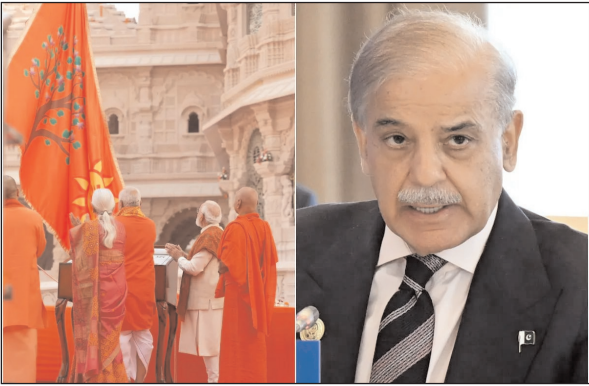
पाकिस्तान की भारत-निंदा की आदत कोई नई नहीं है; यह उसकी कूटनीति एवं संकीर्ण सोच का स्थायी चरित्र बन चुकी है। ऐसा शायद ही कोई अवसर हो जब भारत की कोई शक्ति, बढ़ती साख और सांस्कृतिक उन्नयन का प्रभावी दृश्य उभरे और पाकिस्तान उसमें संकुचित मानसिकता से भरी त्रासद टिप्पणियां न करे, विरोध का वातावरण न बनाए या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल आरोपों का पुलिंदा न खोले। हाल ही में अयोध्याजी में श्रीराम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण समारोह को लेकर उसकी बौखलाहट इसी मानसिक दिवालियापन का ताजा उदाहरण है। भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में संघ लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता। यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता-स्मृति और सांस्कृतिक स्वाभिमान का वह क्षण था जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक घटना का विरोध ही नहीं किया बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र तक ले जाकर शिकायत की, जैसे

जनसरोकारों को प्राथमिकता देने हेतु पत्रकारों की बैठक, निष्पक्ष रिपोर्टिंग का लिया संकल्प

अखंड भारत संदेश गाजीपुर। जनपद के थाना कोतवाली मुहम्मदगंवाद अंतर्गत नगर तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों में उपरती समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन के समक्ष रखने और निष्पक्ष व जिम्मेदार पत्रकारिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से स्थानीय पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को वकील बाड़ी स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार पाण्डेय ने की।बैठक में पत्रकारों ने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और तय किया कि जनहित से जुड़े मुद्दों को तथ्यों, प्रमाणों और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर समाचारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। उनका कहना था कि सशक्त रिपोर्टिंग ही प्रशासन को कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकती है, और इसी से जनता की वास्तविक आवाज सरकार तक



पहुँचती है।पत्रकारों ने कहा कि नगर में टूटी-फूटी सड़कें, पुराने और खतरनाक विद्युत तार, अस्पतालों में अव्यवस्था, साफझूसफाई की कमी तथा विकास कार्यों में हो रही देरी जैसी परेशानियाँ लंबे समय से लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इन मुद्दों से उबाव सामूहिक और संगठित रूप से उठाया जाएगा, ताकि मूलभूत सुविधाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें।बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि पत्रकारिता के मूल मूल्य—नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता—को सर्वोच्च स्थान दिया



रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजुल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज की चली कहावत के अनुसार, पाकिस्तान की यह दखलअंदाजी केवल अस्वीकार्य ही नहीं, बल्कि उसकी दोहरी मानसिकता और

विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता

रैली का हुआ आयोजन

अखंड भारत संदेश भदोही। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जनपद में जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जिलाधिकारी शैलेश कुमार के कुशल मार्गदर्शन व निर्देशन में जिला स्वास्थ्य समिति भदोही द्वारा आयोजित के.एन.पी.जी. कॉलेज परिसर से एचआईवी/एड्स जागरूकता रैली को मुख्य विकास अधिकारी बाल गोवंद शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।रैली में कॉलेज के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सहभागिता की। प्रतिभागियों द्वारा ह्वाभाएं होंगी दरकाना झारुआईवी और एड्स पर होगा सशक्त प्रहारहृदय से संदेशों के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलाया गया।विश्व एड्स दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एचआईवी/एड्स केवल एक स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, जिम्मेदारी



और संवेदनशीलता से जुड़ा विषय है। एचआईवी पूर्णतः छुआछूत से नहीं फैलता, बल्कि सुरक्षित व्यवहार और समय से जांच के माध्यम से इससे बचाव संभव है।आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एक महत्त्वपूर्ण संदेश के साथ एकर हुए हैं। हर वर्ष 01 दिसम्बर को यह दिवस हमें एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए प्रेरणा देता है। यह केवल एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, जिम्मेदारी और मानवता से जुड़ा विषय है।

●●●●●

साइक्लोन दितवाह से श्रीलंका में 212 की मौत, भारत ने बढ़ाया राहत अभियान

श्रीलंका साइक्लोन 'दितवाह' के कारण श्रीलंका में भयानक बाढ़, भूस्खलन और तबाही के बाद रविवार को भी भारत की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी रहा। इस भीषण आपदा में अब तक 212 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 218 लोग अभी भी लापता हैं। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, खराब मौसम के कारण 2,73,606 परिवारों के लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारत की 'नेबरहुड फस्ट' नीति भारत में 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत श्रीलंका को युद्ध स्तर पर मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि ठउम्रह के लगभग 80 जवान श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर राहत अभियान चला रहे हैं।



भारतीय वायु सेना के दो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उ-130ख और क्यू-76, शनिवार को कोलंबो में लगभग 21 टन जरूरी राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं। भारतीय नौसेना का जहाज कटर सुकन्या भी

मानवीय सहायता लेकर विशाखापत्तनम से रवाना हो चुका है और जल्द ही श्रीलंका पहुंचने की उम्मीद है। फंसे हुए भारतीयों सहित 24 यात्रियों को बचाया

भारतीय वायु सेना ने फंसे हुए यात्रियों को बचाने के लिए कई साहसी ऑपरेशन चलाए। IAF हेलीकॉप्टरों ने एक हाइब्रिड बचाव मिशन चलाया, जिसमें गरुड़ कमांडो की मदद से कोटमाले के प्रतिबंधित क्षेत्र से 24 यात्रियों (जिनमें भारतीय और विदेशी नागरिक भी शामिल थे) को सुरक्षित कोलंबो एयरलिफ्ट किया गया। इसी तरह के प्रयास में, तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को भी तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कोलंबो पहुंचाया गया। विमानवाहक पोत कटर विक्रान्त पर सवार दो चेतक हेलीकॉप्टरों ने भी बचाव कार्यों में हिस्सा लिया। शनिवार को एक चेतक टीम ने छत पर फंसे चार लोगों के एक परिवार को सफलतापूर्वक बचाया। कश्मिर ने राहत अभियानों में मदद के लिए दियाथलावा आर्मी कैंप से भूस्खलन प्रभावित कोटमाले इलाके में श्रीलंकाई सेना के 40 जवानों को भी एयरलिफ्ट किया।

बाढ़ से निपटने में विफलता को स्वीकारा, मृतकों की संख्या बढ़कर 162 हुई



अनुतिन ने संवाददाताओं से कहा कि वह बाढ़ प्रबंधन में सरकार की कमियों को स्वीकार रहे हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते समय लोगों से माफी मांगी और कहा कि सरकार उनकी देखभाल और सुरक्षा करने में असमर्थ रही। अनुतिन ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा देना शुरू कर देगी। उन्होंने अतिरिक्त राहत उपायों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें ऋण वसूली को स्थगित करने और मकानों की मरम्मत के लिए अल्पकालिक ब्याज-मुक्त ऋण शामिल हैं। आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह सभी प्रभावित प्रांतों में जलस्तर कम होने लगा। वीडियो फुटेज में स्थानीय निवासी नुकसान का जायजा लेने के लिए अपने जलमग्न घरों की ओर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्नीचर और निजी सामान फर्श पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है।

बांग्लादेश वापस लौटने का फैसला लेना अकेले मेरे बस की बात नहीं

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के स्व निर्वासित कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को कहा कि हबेबद गंभीरद बीमारी से जूझ रही उनकी माँ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलने के लिए उनका वतन वापस लौटना पूरी तरह उनके हाथ में नहीं है। बीएनपी की 80 वर्षीय प्रमुख जिया को छत्ती में संक्रमण के कारण हृदय और दोनों फेफड़े प्रभावित होने के बाद 23 नवंबर को एक निजी



अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल 2008 से लंदन में रह रहे रहमान (60) ने शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि किसी भी बच्चे की तरह वह इस

मुश्किल समय में मां के पास रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन दूसरों की तरह, इस बारे में एकतरफा फैसला लेना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है और

स्टॉकटन के बैंक्वेट हॉल में अंधाधुंध फायरिंग, 4 की मौत, 10 घायल

स्टॉकटन स्टॉकटन के एक बैंक्वेट हॉल में परिवार के एक समारोह के दौरान हुई अंधाधुंध गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। मरने वालों और घायलों में बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ ऑफिस की प्रवक्ता हीथर ब्रेंट ने पुष्टि की कि यह घटना शाम 6 बजे से ठीक पहले हुई। 'टारगेटेड हमला' होने की आशंका प्रवक्ता हीथर ब्रेंट ने मौके पर बताया कि शुरूआती संकेतों से ऐसा लगता है कि यह घटना 'किसी को निशाना बनाकर किया गया हमला' हो सकता है। हालांकि, जांचकर्ता अभी भी संभावित मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।



सैन जोकिन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रॉन प्रीटास ने लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा, 'अगर आपके पास इस हमलावर के बारे में कोई जानकारी है, तो तुरंत संपर्क करें।

और अगर आप वह व्यक्ति हैं, तो तुरंत सरेंडर कर दें।' मेयर ने बताया दुख यह बैंक्वेट हॉल एक ऐसी जगह पर है जो अन्य व्यवसायों के साथ एक पार्किंग लॉट साझा करता है। घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी हालत के बारे में तत्काल कोई और जानकारी नहीं दी है। स्टॉकटन, जिसकी आबादी लगभग 320,000 है, सैक्रामेंटो से लगभग 64 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मेयर क्रिस्टीना फुगाजी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, 'परिवारों को अस्पतालों में अपने प्रियजनों के बचने की प्रार्थना करने के बजाय, इस समय एक साथ होना चाहिए।'

यूएन की पाक को चेतावनी, जल्दबाजी में संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता पर भारी

संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा जल्दबाजी में अपनाए गए संवैधानिक संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। उन्होंने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। क्या है यूएन की मुख्य चिंता? यूएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो बयान में वोल्कर टर्क ने कहा कि 26वें संशोधन की तरह, नवीनतम संवैधानिक संशोधनों को भी कानूनी समुदाय और पाकिस्तानी लोगों के साथ बिना किसी व्यापक चर्चा के अपनाया गया है। टर्क ने कहा, 'इन बदलावों को एक साथ लेने पर, न्यायपालिका को राजनीतिक

हस्तक्षेप और कार्यकारी नियंत्रण के अधीन करने का जोखिम है।' उन्होंने सैन्य जवाबदेही और कानून के शासन के सम्मान के बारे में भी गंभीर चिंताएं जताईं। टर्क ने चेतावनी दी कि इन संशोधनों से लोकतंत्र और कानून के शासन के सिद्धांतों के लिए दूरगामी परिणाम होने का जोखिम है, जिन्हें पाकिस्तानी लोग बहुत प्यार करते हैं। क्या हैं पाकिस्तान के नए संशोधन? पाकिस्तान ने 13 नवंबर को नए संवैधानिक बदलाव अपनाए हैं। न्यायिक शक्ति में बदलाव (27वां संशोधन) किया गया है। इसके तहत, एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया गया है, जिसे अब संवैधानिक मामलों पर सुनवाई का अधिकार होगा। इससे सुप्रीम



कोर्ट की शक्तियां कम हो गई हैं, जो अब सिविल और क्रिमिनल मामले ही देखेगा।

इसके अलावा, सेना प्रमुख असीम मुनीर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए हैं। इससे तीनों सेनाओं का पूरा

कंट्रोल राष्ट्रपति और कैबिनेट से उद्धृत के हाथों में चला गया है। बयान के मुताबिक, 27वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को अपराधिक मामलों और गिरफ्तारी से जीवन भर की छूट मिल गई है। संवैधानिक संशोधन के खिलाफ विरोध पिछले हफ्ते, पाकिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने भी इन संशोधनों का विरोध किया था। कार्टसिल ने कराची प्रेस क्लब के बाहर 27वें संवैधानिक संशोधन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रही अपनी सदस्य फरवा असकर और पत्रकार अलिफिया सोहेल की 'गैर-कानूनी गिरफ्तारी और पाँच घंटे की हिरासत' की निंदा की थी।

'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा

पाकिस्तान पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है. शहबाज सरकार में सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रविवार को कुछ ऐसा कह दिया है जो एक मंत्री पद पर बैठे शख्स को शोभा नहीं देता. उन्होंने इमरान खान की बहनों को 'शर्म से मर जाने' की नसीहत दी है. भारत की मीडिया पर फोड़ ठीकरा खुद को बचाते हुए देश के रसूखदार मंत्री ने ठीकरा भारत की

मीडिया पर फोड़ दिया. उनकी निगाहें इमरान खान की तीनों बहनों पर हैं, लेकिन निशाने पर अफगानी और भारतीय मीडिया है. पाकिस्तानी अखबर डॉन के मुताबिक, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के बयान के आधार पर बताया कि उन्होंने इमरान खान की बहनों की आलोचना की. उन्होंने कहा विरोधी पार्टी पीटीआई हमारी नीतियों का तोड़ नहीं ढूँढ पा रही है इसलिए अनगल तरीके अपना रही है. 'अपने देश के शहीदों की बात नहीं करती'

फिर विदेशी मीडिया पर इमरान की बहनों के बयान को निशाने पर लेते हुए कहा, 'ये बहनें



इंडियन चैनल और अफगानिस्तान के चैनल पर जाकर अपने भाई के लिए क्यों रो रही हैं? लेकिन अपने देश में शहीदों के बारे में बात नहीं कर रही हैं, जाकर एक कैदी

(इमरान खान) के उत्पीड़न के बारे में रो रही हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है?' 'उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए' तारार के मुताबिक इस तरह किसी

दूसरे देश के चैनल पर जाकर अपनी बात रखना गलत है और उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए. वो बोले, 'जो लोग दूसरे देश के चैनल पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि इन्हें विदेशी मीडिया ने प्लेटफॉर्म इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पता था कि "इस परिवार और इस पार्टी की सोच पाकिस्तान के खिलाफ है." इमरान बिल्कुल ठीक: तारार पाकिस्तानी मंत्री ने दावा किया कि परिवार इमरान की सेहत को लेकर "हाइप" बना रहा है. उन्होंने कहा, टमैं आपको यकीन दिलाता हूं: वह ठीक-ठाक हैं. कोई दिक्कत नहीं है.

वह हर दिन एक घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं. इमरान की बहनों की बदसलूकी के वीडियो वायरल हाल ही में इमरान की बहनों ने अदियाला जेल के बाहर अपने भाई से मिलने की मांग उठाते हुए धरना दे दिया था. इसके बाद पीटीआई के दूसरे सदस्य भी इजाजत न मिलने पर वहीं बैठ गए थे. पीटीआई के मुताबिक, अलीमा खान, डॉ. उजमा खान और नोरीन जेल के बाहर शांति से बैठी थीं. उसी दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें हिंसक तरीके से हिरासत में लिया. इसे लेकर कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थीं।

अखंड भारत संदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

स्वामी श्री योगी सत्यम् फॉर योग सत्संग समिति द्वारा विपिन इण्टरप्राइजेज 1/6C माधव कुंज कटरा, प्रयागराज से मुद्रित एवं

क्रियायोग आश्रम एण्ड अनुसंधान संस्थान झुंसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

सम्पादक

स्वामी श्री योगी सत्यम् RNI NO. UPHIN/2001/09025

प्रबन्धक

अनूप मिश्रा

ऑफिस मो.:

9565333000

Email:

akhandbharatsandesh1@gmail.com

सभी विवादो का न्याय क्षेत्र

प्रयागराज होगा

आसिम मुनीर के पास PM और राष्ट्रपति से भी ज्यादा पॉवर, UN ने दिखाया आईना तो तिलमिला उठा पाकिस्तान

पाकिस्तान पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में 27वें संशोधन के तहत आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ाया, जिस पर संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर (मानवाधिकार) वोल्कर टर्क ने सवाल उठाए. वोल्कर टर्क ने कहा कि पाकिस्तान का ये संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करता है, जिसके बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा. दअड विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी संसद ने बहस के बाद ये बदलाव किए हैं, इस पर सुएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश की

यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर ने जेनेवा में जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का संवैधानिक संशोधन पिछले साल के 26वें संशोधन की तरह, कानूनविदों और बड़े सिविल सोसाइटी के साथ बिना किसी सलाह और बहस के अपनाया गया. उन्होंने आगे कहा कि जल्दबाजी में अपनाए गए संशोधन ने न्यायपालिका को कमजोर किया है और सेना की जवाबदेही को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. उनके इसी बयान पर बौखलाए पाकिस्तान ने सफाई पेश की. उसके विदेश मंत्रालय ने कहा, हूपाकिस्तान, सुएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से पाकिस्तान की संसद के दो-

तिहाई बहुमत से पास हुए 27वें संशोधन के बारे में जताई गई आशंकाओं पर ऐतराज जताता है." वोल्कर के बयान में जमीनी हकीकत नहीं: पाकिस्तान दअड विदेश मंत्रालय ने कहा, "दुनिया के दूसरे संसदीय लोकतंत्रों की तरह कानून बनाना और संविधान में बदलाव पाकिस्तान के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों का खास अधिकार क्षेत्र है. पाकिस्तान मानवाधिकार उच्चायुक्त के काम को पूरी अहमियत देता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि जारी किए गए बयान में जमीनी हकीकत नहीं दिखाई गई है. पाकिस्तान की संसद में अपनाए

गए संवैधानिक बदलावों में संविधान में बताए गए सही तरीकों का पालन किया गया है. पाकिस्तान ने कहा कि लोकतंत्र और राजनैतिक तरीके नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की नींव हैं और इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए.हह शहबाज सरकार ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक मानवाधिकार, मानव सम्मान, आजादी और कानून राज की रक्षा करने वाले सिद्धांतों के प्रति समर्पित है. विदेश मंत्री इशाक डार के कार्यालय ने अपील की है कि उनके फैसले का सम्मान किया जाए. पाकिस्तान में विरोध के बीच हुआ 27वां



संविधान संशोधन पाकिस्तान ने हाल ही में 27वें अमेंडमेंट के बड़े विरोध के बीच संसद ने जल्दबाजी में पारित कराया. सबसे बड़ी चिंताओं में संघीय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर न्यायपालिका तंत्र में बड़ा

बदलाव करना और आर्टिकल 243 में बदलाव करना शामिल रहा, जिसमें आर्मी की अहमियत बढ़ी है और आर्मी चीफ को पाकिस्तान की आर्म्ड सर्विसेज में सबसे ऊपर नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर जगह मिली है।